मेसर्स.गणेश सातारकर प्रकाशित

श्रीलंका का संविधान

ISBN: 978-81-685073-8-8

Author: - MR.GANESH SHRIRANG SATARKAR
LL.M
Advocate, Bombay High Court

M/s.Adv.Ganesh Shrirang Satarkar & Co.
Published By This Book
Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932

1. **BOOK TITLE : श्रीलंका का संविधान**
2. **LANGUAGE:** HINDHI
3. **ISBN: 978-81-685073-8-8**
4. **EDITION:** FIRST EDITION
5. **AUTHOR: Mr. GANESH SHRIRANG SATARKAR**
6. **PUBLISHER/ PUBLISHING AGENCY** :-
7. **M/s. INDIAN FARMER AGRO CO.–** SHIVNERI, GAT NO 153, FARANDWADI, MANE MALA TAL PHALTAN, DIST - SATARA. MAHARSHTA, PIN 415523 INDIA
8. **CONTACT DETAILS:**
   MOBILE: +91 7066766607 **EMAIL:** GANESHNALE0@GMAIL.COM
9. **YEAR OF PUBLICATION:** 2026
10. **FORMAT:** SINGLE-COMPONENT RETAIL PRODUCT (BOOK)
11. **PRICE (IN INDIA):** ₹ 10 /- (**Printed and Published in India)**

COPYRIGHT & PUBLICATION STATEMENT

© 2026 **Mr. Ganesh Shrirang Satarkar (Nale)**
All rights reserved.
Disclaimer:
This publication is protected under applicable copyright laws. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, digitized, scanned, transmitted, copied, shared, sold, or circulated in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, audio-visual, digital, or online—without the prior written permission of the author and the publisher, except for brief quotations permitted strictly for academic, educational, research, or review purposes This book has been authored with the sole objective of presenting research-based, educational, and informative content in a clear, responsible, and accessible manner for students, scholars, and general readers. There is no intention whatsoever to offend, defame, misrepresent, or harm the sentiments, beliefs, dignity, or rights of any individual, community, group, culture, religion, or institution. All references are included purely for scholarly discussion. Every effort has been made to ensure accuracy; however, inadvertent errors may occur. Readers are requested to inform the publisher for correction in future editions. Unauthorized reproduction or piracy is punishable under law.

BIOGRAPHY : ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

Adv. Ganesh Shrirang Satarkar is an emerging legal scholar, researcher, and academic contributor working at the intersection of law, criminology, sociology, and digital governance. He is currently associated with the Central University of Haryana, where he is pursuing postgraduate research in sociology alongside his interdisciplinary work in legal studies.

He holds an LL.M. in Criminal Law, LL.B. (Special), and has qualified the UGC-NET in both Law and Criminology. His academic research focuses on criminal justice systems, cybercrime, artificial intelligence in law, media and crime, governance studies, and socio-legal research.

Adv.Ganesh has contributed to national and international academic platforms through research publications, conference papers, and interdisciplinary collaborations. His work explores emerging legal challenges in areas such as digital justice, cyber security, social justice, gender studies, and technological transformations in legal systems.

He is actively connected with several international academic and research platforms including ORCID, Web of Science, SSRN, Vidwan (INFLIBNET), Google Scholar, OSF, and Harvard Dataverse.

Author Bio Researcher Profiles :

1. ResearchIDs : rid131046
2. Orcid Id : https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8474-7432
3. ISNI : https://isni.org/isni/0000000529498911
4. Web of Science ResearcherIDOYE-6264-2025
5. Social science research network SSRN Author ID: 9293272
6. Vidwan Profile URL: https://vidwan.inflibnet.ac.in/profile/666713
7. Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=4MrvCEwAAAAJ
8. OSF ID : https://osf.io/cndj8/
9. harvard.edu : https://dataverse.harvard.edu/dataverse/GANESHSHRIRANGSATARKAR).
10 https://about.me/adv.ganeshsatarkar

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932

ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

CERTIFICATE

OF WORLD RECORD

Proudly Presented To

Ganesh Shrirang Satarkar

In recognition of the outstanding achievement of becoming the First Indian to Translate and Publish the Constitutions of All 54 African Countries into Hindi as Separate ISBN-Registered Books, demonstrating exceptional dedication, scholarly excellence, and a significant contribution to legal literature and linguistic accessibility, thereby establishing a distinguished and historic record of academic accomplishment.

We officially announce the above-mentioned candidate as a globally certified **"Inspiration World Record Holder"**.

The certificate was issued on 27th February, 2026.

INSPIRATION IS WHERE PASSION BECOMES LEGACY

CERTIFIED

Application No. IWR/2026/UR0173
Certificate No. IWR/2026/WRH0081
Issued By: Chief Adjudicator

ISO CERTIFIED

VISHWAGURU ARPANAM 2026

VIA2025/SS-VA2025AZ760-2025-170/09102025

2 025100 900010

ISO 9001:2015 Registration No: QT-56622/0925
Micro, Small, and Medium Enterprises Registration Number: 11-0093948
Trademark Registered Under the Act of "TRADE MARKS ACT, 1999"

© www.inspirationworldrecords.org

श्रीलंका का संविधान

1. देश का नाम

Sri Lanka (श्रीलंका)

---

2. संविधान का नाम

श्रीलंका का संविधान, 1978
(2015 तक संशोधित)

---

3. संविधान के अध्याय (Chapters)

श्रीलंका के संविधान में कुल **24 अध्याय (Chapter I से XXIV तक)** हैं:

1. जनता, राज्य और संप्रभुता
2. बौद्ध धर्म
3. मौलिक अधिकार
4. भाषा
5. नागरिकता
6. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य
7. कार्यपालिका (राष्ट्रपति)
   7A. संवैधानिक परिषद
8. कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद)
9. कार्यपालिका (लोक सेवा)
10. विधायिका (संसद)
11. विधायिका की प्रक्रिया एवं शक्तियाँ
12. संविधान संशोधन
13. जनमत संग्रह
14. निर्वाचन एवं मताधिकार
    14A. चुनाव आयोग
15. न्यायपालिका
    15A. न्यायिक सेवा आयोग
16. उच्च न्यायालय
17. वित्त
    17A. प्रांतीय परिषद
18. सार्वजनिक सुरक्षा
    18A. राष्ट्रीय पुलिस आयोग

19. लोकपाल (Ombudsman)
    19A. भ्रष्टाचार जांच आयोग
    19B. राष्ट्रीय खरीद आयोग
20. सामान्य प्रावधान
21. संक्रमणकालीन प्रावधान
22. व्याख्या
23. निरसन
24. संविधान की उद्घोषणा

---

4. संविधान के अनुच्छेद (Articles)

- कुल लगभग **172 अनुच्छेद**
- अनुच्छेद संख्या: **अनुच्छेद 1 से 172 तक**

---

5. अध्यायों का संक्षिप्त विवरण

अध्याय 1:
राज्य, संप्रभुता, क्षेत्र और राष्ट्रीय प्रतीकों का वर्णन

अध्याय 2:
बौद्ध धर्म को विशेष स्थान

अध्याय 3:
मौलिक अधिकार – समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा

अध्याय 4:
भाषा नीति (सिंहला और तमिल)

अध्याय 5:
नागरिकता के नियम

अध्याय 6:
नीति निर्देशक सिद्धांत और कर्तव्य

अध्याय 7:
राष्ट्रपति की शक्तियाँ

अध्याय 7A:
संवैधानिक परिषद

अध्याय 8:
मंत्रिपरिषद और शासन

अध्याय 9:
लोक सेवा प्रणाली

अध्याय 10:
संसद की संरचना

अध्याय 11:
कानून बनाने की प्रक्रिया

अध्याय 12:
संविधान संशोधन प्रक्रिया

अध्याय 13:
जनमत संग्रह

अध्याय 14:
चुनाव प्रणाली

अध्याय 14A:
चुनाव आयोग

अध्याय 15:
न्यायपालिका

अध्याय 15A:
न्यायिक सेवा आयोग

अध्याय 16:
उच्च न्यायालय

अध्याय 17:
वित्तीय प्रावधान

अध्याय 17A:
प्रांतीय परिषद

अध्याय 18:
सार्वजनिक सुरक्षा

अध्याय 18A:
पुलिस आयोग

अध्याय 19:
लोकपाल

अध्याय 19A:
भ्रष्टाचार आयोग

अध्याय 19B:
खरीद आयोग

अध्याय 20–24:
सामान्य, संक्रमण, व्याख्या, निरसन और उद्घोषणा

---

6. श्रीलंका के संविधान का समग्र विवरण

श्रीलंका का संविधान 1978 में लागू किया गया और यह देश के शासन, प्रशासन तथा नागरिकों के अधिकारों का मूल आधार है। यह संविधान एक **एकात्मक (Unitary) राज्य व्यवस्था** को स्थापित करता है, जिसमें सभी शक्तियाँ मुख्य रूप से केंद्र सरकार के पास होती हैं।

इस संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें **राष्ट्रपति प्रणाली (Presidential System)** को अपनाया गया है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख और कार्यपालिका का प्रमुख होता है। उसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिससे उसे लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त होती है। राष्ट्रपति के पास व्यापक शक्तियाँ होती हैं, जैसे मंत्रियों की नियुक्ति, संसद को भंग करना, और राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना।

संविधान की प्रस्तावना में देश के मूल आदर्शों और उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। पहला अध्याय राज्य की संप्रभुता, क्षेत्र और राष्ट्रीय प्रतीकों को परिभाषित करता है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि संप्रभुता जनता में निहित है और वही अंतिम सत्ता का स्रोत है।

दूसरा अध्याय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें **बौद्ध धर्म को विशेष स्थान** दिया गया है। हालांकि, संविधान अन्य धर्मों की स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करता है, जिससे धार्मिक सहिष्णुता बनी रहती है।

तीसरे अध्याय में नागरिकों के **मौलिक अधिकारों** का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, और यातना से सुरक्षा जैसे अधिकार शामिल हैं। यह अध्याय लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है और नागरिकों को राज्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।

चौथा अध्याय भाषा से संबंधित है, जिसमें सिंहला और तमिल को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। यह प्रावधान देश की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

पाँचवां अध्याय नागरिकता से संबंधित है, जिसमें नागरिक बनने और नागरिकता खोने के नियमों का वर्णन किया गया है।

छठा अध्याय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों को प्रस्तुत करता है। ये सिद्धांत सरकार को सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और कल्याणकारी राज्य की दिशा में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। हालांकि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

कार्यपालिका का विस्तृत वर्णन सातवें और आठवें अध्याय में किया गया है। राष्ट्रपति के साथ-साथ मंत्रिपरिषद भी शासन का हिस्सा है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है और सरकार के कार्यों का संचालन करता है।

विधायिका के रूप में संसद कार्य करती है, जो कानून बनाने की जिम्मेदारी निभाती है। संसद के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। संविधान में विधायी प्रक्रिया, मतदान, कोरम, और विधेयकों के पारित होने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है।

न्यायपालिका संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। सर्वोच्च न्यायालय और अपील न्यायालय देश के प्रमुख न्यायिक संस्थान हैं।

संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी दी गई है, जिससे समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता होती है।

श्रीलंका के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें **प्रांतीय परिषदों** की व्यवस्था की गई है, जिससे शासन में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है।

इसके अतिरिक्त, संविधान में विभिन्न स्वतंत्र आयोगों की स्थापना की गई है, जैसे चुनाव आयोग, पुलिस आयोग और भ्रष्टाचार विरोधी आयोग। ये संस्थाएँ शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं।

संविधान में वित्तीय प्रावधान भी शामिल हैं, जो संसद को सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण प्रदान करते हैं।

अंततः, श्रीलंका का संविधान एक व्यापक और संतुलित दस्तावेज है, जो लोकतंत्र, मानवाधिकारों और कानून के शासन को सुनिश्चित करता है। यह देश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का आधार है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

M/s.Adv.Ganesh Shrirang Satarkar & Co.
Published By This Book

THE END

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932